बैंक-बीमा से देर से पॉलिसी सरेंडर करने पर मिलेगा ज्यादा मूल्य, इरडा ने अधिसूचित किए नियम

नई दिल्ली ।

पॉलिसीधारक जितनी देर से अपनी जीवन बीमा पॉलिसी सरेंडर करेंगे, उन्हें उतना ही ज्यादा मूल्य मिलेगा। इसके लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने विभिन्न नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें बीमा पॉलिसी वापस या सरेंडर करने से जुड़ा शुल्क भी शामिल है। बीमा कंपनियों को ऐसे शुल्कों का खुलासा पहले ही करना होता है। ये नियम एक अप्रैल, 2024 से प्रभाव में आएंगे। इरडा (बीमा उत्पाद) विनियमन-2024 के तहत छह नियमों को एक एकीकृत ढांचे में मिलाया गया है। इसका मकसद बीमा कंपनियों को उभरती बाजार मांग के अनुसार तेजी से कदम उठाने में सक्षम बनाना, कारोबार सुगमता बेहतर करना व बीमा को बढ़ावा देना है।

ऐसे समझें - नए नियम के तहत अगर पॉलिसी खरीद के तीन साल के भीतर लौटाई या वापस की जाती है, तो सरेंडर मूल्य समान या उससे भी कम रह सकता है। पॉलिसी को चौथे से सातवें वर्ष तक वापस करने पर सरेंडर मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है। सरेंडर मूल्य का मतलब बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारक को परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी समाप्त करने पर भुगतान की गई राशि से है। अगर पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के बीच सरेंडर करता है तो उसे कमाई और बचत हिस्से का भुगतान किया जाता है।

34 की जगह छह नियम, दो नए - इरडा ने कहा, यह नियामकीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 34 नियमों को छह नियमों के साथ बदला गया है। साथ ही, नियामकीय परिदृश्य में स्पष्टता को लेकर दो नए नियम लाए गए हैं। बीमा नियामक ने कहा, नएनियम का मकसद पॉलिसी वापसी पर गारंटीशुदा मूल्य और विशेष वापसी मूल्य से जुड़े नियमों को मजबूत करना है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया है कि बीमाकर्ता प्रभावी निगरानी और उचित जांच-परख के लिए ठोस गतिविधियां अपनाए।

इरडा ने 19 मार्च को हुई बैठक में बीमा क्षेत्र के लिए नियामकीय ढांचे की व्यापक समीक्षा के बाद आठ सिद्धांत आधारित एकीकृत नियमों को मंजूरी दी।

इंडिगो अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मार्गों पर अपनी सेवाएं दोगुनी करेगी, एयरलाइन के सीईओ ने कही यह बात

नई दिल्ली । इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि उनका लक्ष्य नए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों के साथ 2030 तक कंपनी की सेवाओं का आकार दोगुना करना है। घरेलू बाजार में 60 फीसदी से कुछ अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ए321 एक्सएलआर विमान खरीदने पर भी बड़ा दांव लगा रही है। यह विमान 2025 में कंपनी के बेड़े का हिस्सा बन सकती है। एल्बर्स ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने और उसका विस्तार करने की कोशिश करते हुए साक्षात्कार में कहा कि इंडिगो के लिए अगली बड़ी छलांग दशक के अंत तक अपने आकार को दोगुना करने की होगी। अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए, इंडिगो प्रमुख ने कहा कि सीट क्षमता को दोहरे अंक में ले जाना है और हर हफ्ते एक विमान आ रहा है। आपूर्ति श्रृंखला के साथ-साथ प्रैट एंड व्हिटनी इंजन संकट के बीच, एल्बर्स ने यह भी जोर दिया कि एयरलाइन बहुत सारे उपाय कर रही है जो कि कारगर साबित हो रहे हैं। 17 साल पुराना इंडिगो एयरलाइन 88 घरेलू और 33 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों के लिए उड़ान भरता है। इसके पास 360 से अधिक विमानों का बेड़ा है। वर्तमान में, इंडिगो के पास तुर्की एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, कतर एयरवेज, अमेरिकन एयरलाइन, केएलएम-एयरफ्रांस, क्वांटास, जेटस्टार और वर्जिन अटलांटिक के साथ कोडशेयर हैं। कोडशेयरिंग एक एयरलाइन को अपने यात्रियों को अपने साझेदार एयरलाइनों पर बुक करने और विभिन्न गंतव्यों के लिए सहज यात्रा सुविधा प्रदान करने की अनुमति देता है।

2023-24 के अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में सीएडी घटकर 10.5 अरब डॉलर, आरबीआई के जारी आकंड़ों में क्या खास

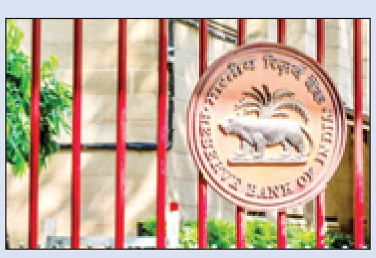

नई दिल्ली । वित्त वर्ष 2023-24 की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में देश का चालू खाते का घाटा घटकर 10.5 अरब डॉलर यानी जीडीपी का 1.2 प्रतिशत रहा है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। इससे पिछली जुलाई-सितंबर तिमाही में यह 11.4 अरब डॉलर और एक साल पहले 2022-23 की अक्तूबर-दिसंबर में 16.8 अरब डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार में हुई बढ़ोतरी वहीं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) अप्रैल-दिसंबर 2023 में 8.5 अरब डॉलर रहा था। एक साल पहले 2022-23 की इसी अवधि में यह 21.6 अरब डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में छह अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में 11.1 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी। वस्तु व्यापार घाटा में मामूली बढ़ोतरी वस्तु व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2023-23 की तीसरी तिमाही के दौरान 71.6 अरब डॉलर रहा, जो 2022-23 की इसी तिमाही में 71.3 अरब डॉलर से थोड़ा ज्यादा है। वित्तीय खाते के स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 4.2 अरब डॉलर का शुद्ध प्रवाह हुआ। यह 2022-23 की तीसरी तिमाही के दो अरब डॉलर के शुद्ध प्रवाह का दोगुने से भी अधिक है।

सोने में तेजी, चांदी की कीमतों में गिरावट

नई दिल्ली । घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। सोने की कीमतों में तेजी

आई है जबकि चांदी के दाम गिरे हैं। वहीं वायदा कीमतों में भी बढ़त रही। चांदी के वायदा भाव नीचे आये हैं। चांदी के वायदा भाव 74,450 रुपये के करीब कामकाज कर रहे थे। सोना 61,150 रुपये के करीब कारोबार कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी के वायदा भाव की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। जबकि सोने के वायदा भाव में भी बढ़त रही। सोने के वायदा भाव आज तेजी के साथ खुले। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्सा) पर सोने का बेंचमार्क अप्रैल अनुबंध आज 85 रुपये की बढ़त के साथ ही 66,198 रुपये पर खुला। सोने का वायदा भाव गत सप्ताह 66,943 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव के शीर्ष स्तर पर पहुंचा था। दूसरी ओर चांदी के वायदा भाव की शुरुआत भी गिरावट के साथ हुई। एमसीएक्सा पर चांदी का बेंचमार्क मई अनुबंध 31 रुपये टूटकर 74,487 रुपये के भाव पर खुला। इस समय ये इतने 74,493 रुपये के भाव पर दिन के उच्च और 74,400 रुपये प्रति किलो के भाव पर दिन के निचले स्तर पर था।

6.8 फीसदी की रफ्तार से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, एसएंडपी ने 2024-25 के लिए बढ़ाया भारत का विकास दर अनुमान

नई दिल्ली ।

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद और उसकी तेज रफ्तार को देखते हुए दुनियाभर की बड़ी रेटिंग एजेंसियां भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ा रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल ने भी अगले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के लिए भारत के विकास दर अनुमान को 0.4 फीसदी बढ़ाकर 6.8 फीसदी कर दिया है। एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में मजबूत घरेलू गतिविधियों के बीच 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.4 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया था।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से 2023-24 में आर्थिक वृद्धि दर उम्मीद से बेहतर 7.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाए जाने के बाद एसएंडपी ने 2024-25 के लिए विकास दर में बढ़ोतरी की है। रेटिंग एजेंसी ने जारी रिपोर्ट में कहा, एशिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए हम आमतौर पर मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाते हैं। इनमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपीन और वियतनाम सबसे आगे हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी अर्थव्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर घरेलू मांग पर आधारित हैं। इन देशों में घरेलू खर्च करने की क्षमता पर उच्च ब्याज दरों और महंगाई का प्रभाव देखने को मिला है, जिसने दूसरी छमाही में जीडीपी की वृद्धि को कम किया है। फिर भी, उम्मीद है कि 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8 फीसदी हो जाएगी।

महंगाई...4.5 फीसदी पर आने की उम्मीद

महंगाई के मोर्चे पर अमेरिकी एजेंसी ने कहा, खुदरा मुद्रास्फीति के 2024-25 में घटकर औसतन 4.5 फीसदी पर आने की उम्मीद है। वहीं, गैर-खाद्य उपभोक्ता महंगाई करीब 250 आधार अंक घट गई है। खाद्य महंगाई चालू वित्त वर्ष के शुरुआती 10 महीने में 40 आधार अंक बढ़ी है। इन उतार-चढ़ाव के बावजूद मुख्य महंगाई चालू वित्त वर्ष में घटकर 5.5 फीसदी रह जाएगी, जो 22-23 में 6.7 फीसदी रही थी।

रेपो दर...75 आधार अंक तक कटौती संभव

एसएंडपी ने कहा, उच्च ब्याज दरों की वजह से

अगले वित्त वर्ष में घरेलू मांग प्रभावित होगी। घरेलू मांग में गिरावट न आए, इसलिए आरबीआई 2024-25 के दौरान रेपो दर में 75 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है। यह कटौती बड़े पैमाने पर इस साल की दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। नरम महंगाई, कम राजकोषीय घाटा व अमेरिका में कम ब्याज दरें आरबीआई के लिए दरों में कटौती शुरू करने का आधार बनाएंगी।

वित्तीय क्षेत्र को मजबूत व पारदर्शी बना रहे आरबीआई के सख्त कदम

एसएंडपी का कहना है कि वित्तीय क्षेत्र में संचालन व्यवस्था और पारदर्शिता में सुधार के लिए आरबीआई गंभीर प्रतिबद्धता दिखा रहा है। उसके उपाय बैंकों को अधिक मजबूत और पारदर्शी बना रहे हैं। केंद्रीय बैंक की ओर से हाल में किए गए ये उपाय वित्तीय संस्थानों के अति उत्साह को कम करेंगे। नियमों के अनुपालन की संस्कृति को बढ़ाएंगे और ग्राहकों के हितों की रक्षा करेंगे।

एसएंडपी ग्लोबल में क्रेडिट विश्लेषक गीता चुघ ने कहा, आरबीआई नियमों का अनुपालन नहीं होने, ग्राहक शिकायतों, आंकड़ों की गोपनीयता, कामकाज, केवाईसी और मनी-लॉन्ड्रिंग निरोधक मुद्दों को लेकर ज्यादा सख्त है। केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक रूप से उन प्रमुख मुद्दों का खुलासा करने का निर्णय लिया है, जो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ निलंबन या अन्य सख्त कार्रवाई का कारण बनते हैं। वह उन गतिविधियों की निंदा करने में भी अधिक मुखर हो गया है, जो ग्राहकों और निवेशकों के हितों के लिए नुकसानदायक हैं।

ये उपाय किए गए

आईआईएफएल फाइनेंस लि. को गोल्ड लोन और जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लि. को शेयरों के बदले कर्ज देने से रोकना।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक लि. (पीपीबीएल) पर नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाना।

बार-बार तकनीकी गड़बड़ी के बाद दिसंबर, 2020 में एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर पाबंदी।

ये कदम नियमों के उल्लंघनों को लेकर लगाए जाने वाले नाममात्र के वित्तीय जुर्माने से अलग हैं।

चिंता...सख्ती से बढ़ सकती है पूंजी लागत

चुघ ने कहा, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। हालांकि, इन नियामकीय उपायों को लेकर जोखिम भी है। इससे वृद्धि बाधित हो सकती है और वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी की लागत बढ़ सकती है।

पांच लाख टन रबी प्याज खरीदेगी केंद्र सरकार, उपभोक्ता मामलों के सचिव ने बताई इसकी वजह

नई दिल्ली ।

प्याज निर्यात प्रतिबंध के मद्देनजर मंडी की कीमतों में संभावित गिरावट की चिंता के बीच केंद्र ने किसानों को आश्वासन दिया कि वह अगले 2-3 दिनों में पांच लाख टन प्याज की खरीद शुरू करेगी। पिछले हफ्ते वाणिज्य मंत्रालय ने प्याज निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। प्याज शिपमेंट पर रोक 31 मार्च तक वैध थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी चिंता का ध्यान रखा जाएगा। हम बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए अगले 2-3 दिनों में 5 लाख टन रबी (सर्दियों) की फसल की खरीद शुरू करेंगे।

किसानों के हितों की रक्षा हम करेंगे- रोहित कुमार

पत्रकारों से बातचीत करते हुए उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने कहा कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध से व्यापारियों पर असर पड़ रहा है, न कि किसानों पर क्योंकि महाराष्ट्र में औसत मंडी (थोक) कीमतें वर्तमान में लगभग 13-15 रुपये प्रति किलोग्राम हैं, जो पिछले वर्ष के स्तर से लगभग दोगुनी है। उन्होंने कहा, भले ही कीमतें गिरें, हम किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। सचिव ने कहा कि सरकार आम तौर पर मौजूदा बाजार दर पर बफर स्टॉक के लिए प्याज खरीदती है। हालांकि, यदि दरें उत्पादन लागत से नीचे आती हैं, तो सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उनकी लागत कम से कम कवर हो।

औसत खुदरा कीमतें वर्तमान में 33 रुपये प्रति किलोग्राम- रोहित

2023-24 में सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 17 रुपये प्रति किलोग्राम की औसत दर पर 6.4 लाख टन प्याज (रबी और खरीफ दोनों फसलें) खरीदा था। उन्होंने कहा कि लगभग पूरी मात्रा का निपटान कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अधिकारी निधि खरे ने कहा कि पिछले साल प्याज की खरीद जून में की गई थी, लेकिन इस साल यह अगले दो दिनों में जल्दी शुरू होने जा रही है। खुदरा कीमतों पर रबी प्याज उत्पादन में संभावित गिरावट के प्रभाव के बारे में सचिव ने कहा कि देश में औसत खुदरा कीमतें वर्तमान में 33 रुपये प्रति किलोग्राम पर स्थिर हैं।

बाल्टीमोर ब्रिज हादसे से भारत में कोयला संकट गहरा सकता है, जानकारों ने जताई आशंका

नई दिल्ली ।

अमेरिका के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट पुल के ढहने की गूंज पूरे भारतीय कोयला और पेटकोक बाजारों में सुनाई दे रही है। इससे आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और मूल्यों पर असर पड़ने की चिंता पैदा हो गई है। एसएंडपी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के अनुसार, एक जहाज की टक्कर से कोयला निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बाल्टीमोर हार्बर के माध्यम से परिचालन स्थगित हो गया है।

अमेरिकी थर्मल कोयले का एक प्रमुख आयातक भारत पुल ढहने के बाद अपनी आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों का सामना कर रहा है। अमेरिका स्थित एक व्यापारी के अनुसार, इस घटना से आर्क कोल के शिपमेंट के प्रतिबंधित होने और भारतीय आयातकों के लिए रसद बाधाएं पैदा होने की उम्मीद है।

एक ब्रोकर ने एसएंडपी को बताया, यह घटना आर्क कोल से एनएपीपी शिपमेंट को प्रतिबंधित करेगी और भारत के लिए आपूर्ति श्रृंखला में कई समस्याएं पैदा करेगी। यूरोप में थर्मल कोयले पर इसका असर पड़ेगा। भारत पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। पेटकोक की कीमतों में उछाल देखकर ऐसा लग रहा है! हालांकि, भारतीय

बाजार के कारोबारियों की मूल्य निर्धारण पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में मिश्रित राय है। एक भारतीय व्यापारी ने कहा, अधिकारियों को यह आकलन करने में 6-7 दिन लगेंगे कि घटना से कितना मलबा है और कितना ड्राफ्ट जमा है। क्योंकि अगर ड्राफ्ट कम है तो यह समस्या हो सकती है। अधिकारियों को मलबा हटाने में 10-15 दिन लग सकते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि इस अवधि के दौरान जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। बाल्टीमोर बंदरगाह, अमेरिकी थर्मल कोयला निर्यात के लिए एक प्रमुख लोडिंग स्थान है। यह भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ

नई दिल्ली ।

घरेलू बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। कुछ राज्यों में पेट्रोल-डीजल महंगा हुआ। महाराष्ट्र में पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे की बढ़त रही जिसके बाद यहां पेट्रोल 104.37 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है जबकि डीजल के दाम 23 पैसे बढ़े हैं और यह 90.89 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

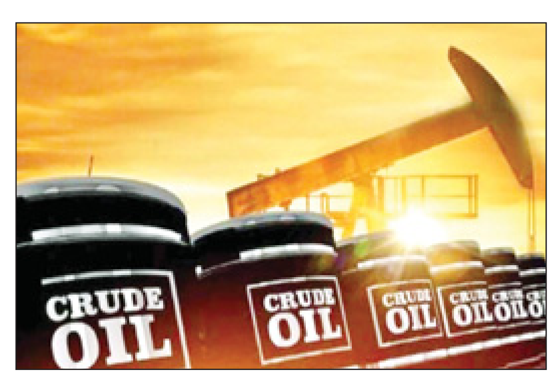

वहीं, बिहार में पेट्रोल 19 पैसे बढ़कर 107.31 रुपये प्रति लीटर हो गया है जबकि डीजल 18 पैसे बढ़कर 94.02 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। इसके अलावा आंध्रप्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान,तेलंगाना और यूपी में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। वहीं, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश, मणिपुर, तामिलनाडु और त्रिपुरा में पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटी हैं।

प्रदेश के नोएडा में पेट्रोल 94.81 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.94 रुपये प्रति लीटर, गुरुग्राम: पेट्रोल 95.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.03 रुपये प्रति लीटर पर हैं। बेंगलुरु में पेट्रोल 99.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल 85.92 रुपये प्रति लीटर, चंडीगढ़: पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर। हैदराबाद: पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर, जयपुर: पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर पर है। पटना में पेट्रोल 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर, लखनऊ: पेट्रोल 94.63 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.74 रुपये प्रति लीटर पर है। चारों महानगरों की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल 87.66 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104.19 रुपये और डीजल 92.13 रुपये प्रति लीटर है। वहींकोलकाता में पेट्रोल की कीमत 103.93 रुपये और डीजल 90.74 रुपये प्रति लीटर है। वहीं. चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.73 रुपये और डीजल 92.32 रुपये प्रति लीटर है।

आर्थिक वृद्धि से जुड़े हाइप पर विश्वास करना बड़ी भूल, पूर्व आरबीआई गवर्नर ने दी ये चेतावनी

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत अपनी मजबूत आर्थिक वृद्धि को लेकर हाइप पर विश्वास करके बड़ी भूल कर रहा है क्योंकि महत्वपूर्ण संरचनात्मक खामियां हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। राजन ने एक साक्षात्कार में कहा कि नई सरकार के लिए चुनावों के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वह है कार्यबल की शिक्षा और कौशल में सुधार करना।

उन्होंने कहा, एक ऐसे भारत में जहां 1.4 बिलियन आबादी में से आधे से अधिक 30 वर्ष से कम आयु के हैं। कार्यबल की शिक्षा और कौशल को ठीक किए बिना, देश को अपनी युवा आबादी का लाभ उठाने में संघर्ष करना पड़ेगा।

आर्थिक प्रचार पर विश्वास करना देश के लिए सबसे बड़ी गलती होगी: राजन

उन्होंने कहा, प्रचार पर विश्वास करना देश के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। प्रचार वास्तविक हो यह सुनिश्चित करने के लिए हमें कई और वर्षों की कड़ी मेहनत करनी है। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कुछ राजनेता चाहते हैं कि आप प्रचार पर विश्वास करें लेकिन भारत के लिए इस विश्वास के आगे झुकना एक गंभीर गलती होगी। भारत को

2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षा को खारिज करते हुए राजन ने कहा कि इस लक्ष्य की बात करना बकवास है। ऐसे में जबकि आपके कई बच्चों के पास हाई स्कूल की शिक्षा नहीं है और ड्रॉप-आउट दर अधिक है। राजन बोले- बढ़ता हुआ कार्यबल तभी लाभप्रद जब वे अच्छी नौकरियों में कार्यरत हों राजन ने कहा, हमारे पास एक बढ़ता हुआ कार्यबल है, लेकिन वह केवल तभी लाभप्रद हो सकता है जब वे अच्छी नौकरियों में कार्यरत हों। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत को अपने श्रमबल को रोजगार के काबिल बनाने की जरूरत है, और दूसरा अपने कार्यबल के लिए रोजगार पैदा करना है। राजन ने उन अध्ययनों का हवाला दिया जो दिखाते हैं कि महामारी के बाद भारतीय स्कूली बच्चों की सीखने की क्षमता में 2012 से पहले के स्तर तक गिरावट आई है और ग्रेड तीन के केवल 20.5 प्रतिशत छात्र ही ग्रेड दो का पाठ पढ़ सकते हैं। भारत में साक्षरता दर वियतनाम जैसे अन्य एशियाई साथियों से भी नीचे है। भारत को 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए और काम करने की जरूरत उन्होंने कहा, यह उस तरह की संख्या है जिससे हमें चिंतित होना चाहिए। मानव पूंजी की कमी दशकों तक हमारे साथ रहेगी। राजन ने अर्थव्यवस्था की संभावनाओं के बारे में हाल में जताई गई उम्मीदों पर आशंका जताते हुए कहा कि भारत को 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए और काम करने की जरूरत है। विदेशी निवेशक तेजी से विस्तार का लाभ उठाने के लिए भारत आ रहे हैं, जो सरकार का अनुमान है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में 7 प्रतिशत से अधिक तक पहुंच जाएगा, जिससे यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगी। राजन ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के लिए वार्षिक बजट की तुलना में चिप विनिर्माण के लिए सब्सिडी पर अधिक खर्च करने का नीतिगत विकल्प गुमराह करने वाला है। भारत में परिचालन स्थापित करने के लिए सेमीकंडक्टर व्यवसायों को अनुमानित रूप से 760 अरब रुपये (9.1 बिलियन डॉलर) सब्सिडी के रूप में दिया जाना है ।

लग्जरी मकानों की बिक्री में 51 फीसदी इजाफा, 2023 में 4,319 करोड़ रुपये तक पहुंचा था मूल्य

नई दिल्ली । मजबूत मांग के कारण 2023 में 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक कीमत के लग्जरी मकानों की बिक्री मूल्य के हिसाब से 51 फीसदी बढ़कर 4,319 करोड़ रुपये पहुंच गई। इस दौरान कम-से-कम 45 लग्जरी मकान बिके। 2022 में इस मूल्य वर्ग में 2,859 करोड़ रुपये कम-से-कम 29 मकान बिके थे। रियल एस्टेट सलाहकार जेएलएल इंडिया के मुताबिक, 2023 में बिके लग्जरी मकानों में बंगला और अपार्टमेंट दोनों शामिल हैं। इसमें प्राथमिक बाजार और पुनर्बिक्री (रीसेल) लेनदेन भी शामिल हैं। इसमें कोई उपहार और संयुक्त उद्यम लेनदेन शामिल नहीं हैं। 14 मकान 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के जेएलएल इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री सामंतक दास ने कहा, 2023 में बिके 45 लग्जरी मकानों में से 14 घर 100 करोड़ और उससे अधिक कीमत के थे। इनमें से अधिकतर 79 फीसदी मुंबई में बेचे गए।

मेसर्स दैनिक नईदुनिया के लिए प्रकाशक अपूर्व तिवारी के द्वारा 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल- 462011 से प्रकाशित एवं मुद्रक डॉ. विश्वास तिवारी के द्वारा नईदुनिया प. प्रा.लि., 2, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल-462011 से मुद्रित। प्रबंध संपादक: डॉ. सुरेन्द्र तिवारी एवं संपादक: अपूर्व तिवारी। *

फोन-0755-2550900-01,-03, फैक्स नं.- 0755-2553914 e-mail : naidunia@gmail.com (* समाचार पत्र से संबंधित सभी प्रकार के विवादों के लिए न्याय क्षेत्र सिर्फ भोपाल होगा।) रजिस्टर्ड नं.म.प्र./296/भोपाल/2012-2014 आर.एन.आई. रजि. क्र. 47694/88, डाक पंजीयन क्र. म.प्र./भोपाल/296/2015-2017